बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!
सक्षम भारत
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित
www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com
Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI
● वर्ष: 23 ● अंक: 186 ● नई दिल्ली ● वीरवार 24 जुलाई 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें
E-mail : rmsdp@hotmail.com
अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

दक्षिण दिल्ली में खत्म होगी बिजली किल्लत, सरकार ने तैयार किया मास्टरप्लान; आधुनिक तकनीक से होगी आपूर्ति

नई दिल्ली। (वेबवार्ता) दिल्ली सरकार ने दक्षिण दिल्ली के लोगों को बिजली कटौती से राहत देने के लिए मास्टर प्लान बनाया है। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ने मेहरौली में 220 केवी सब-स्टेशन को करीब 10.26 करोड़ रुपये खर्च कर आधुनिक तकनीकों से लैस करने का निर्णय लिया है। इससे लोगों को बिजली कटौती या वोल्टेज की समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी। दिल्ली सरकार के उपक्रम दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ने मेहरौली में 220 केवी और 66 केवी के सब-स्टेशनों के लिए नए कंट्रोल एंड रिले (सीएंडआर) पैनल लगाने और पूरे सब स्टेशन को ऑटोमेटिक बनाने का काम शुरू किया है।

दिल्ली की बिगड़ती परिवहन व्यवस्था पर कांग्रेस का हमला

नई दिल्ली।

दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को लेकर सियासत गरमाती नजर आ रही है. लगातार घटती बस सेवाएं, ओवरएज वाहन और जनता की बढ़ती परेशानियों के बीच कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा और पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है. राजीव भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली की बदहाल परिवहन स्थिति को लेकर सरकार की नीयत और नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए.

परिवहन व्यवस्था चरमराई, जनता बेहाल

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हारून यूसुफ ने दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की बदहाली को लेकर आप और भाजपा दोनों सरकारों को घेरा. उन्होंने कहा कि राजधानी को 12-14 हजार बसों की जरूरत है, जबकि हाल में सिर्फ 400 नई बसें चलाई गई. पिछले डेढ़ साल में 2,400 बसें हटा दी गई और मार्च तक 1,700 और हटाई जाएंगी.उन्होंने बताया कि डीटीसी की हालत खराब है, 99% बसें ओवरएज हैं और यात्रियों की संख्या 2012-13 के 46.77 लाख से घटकर अब 25 लाख रह गई है. यूसुफ ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने 11 साल में एक भी नई डीटीसी बस नहीं जोड़ी.

कांग्रेस के समय में सीएनजी और लो-फ्लोर बसों से मिली मजबूती

उन्होंने कहा की सीएजी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के कुल 814 बस रूटों में से 43 प्रतिशत में कटौती कर केवल 468 रूटों पर ही संचालन हो रहा है. डीटीसी का घाटा जहां 2022 में 60,750 करोड़ था, वहीं 2025 तक यह बढ़कर 65,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की आशंका है. उन्होंने कहा कि डीटीसी को अपनी लागत का 57 प्रतिशत हिस्सा केवल कर्ज के ब्याज में देना पड़ता है, जो हर वर्ष बढ़ता जा रहा है. कांग्रेस ने मांग की है कि भाजपा सरकार को डीटीसी को कर्ज मुक्त कर देना चाहिए, जैसा कि कांग्रेस सरकारों ने पहले भी किया था. यूसुफ ने याद दिलाया कि 2010 में कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान पूरी बस सेवा को सीएनजी आधारित बनाया, लो-फ्लोर बसें शुरू कीं और डीटीसी के 18,000 कर्मचारियों को स्थायी किया. उन्होंने मौजूदा परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए डीटीसी को आर्थिक मजबूती देने और नए बसों को जोड़ने की जरूरत बताई.

महिलाओं के लिए पिंक बसों की मांग

कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. ओनिका मेहरोत्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महिलाओं को मिल रही बस सुविधाओं को धीरे-धीरे खत्म कर रही है. उन्होंने कहा कि डीटीसी बसों में सीसीटीवी की कमी है और 'सहेली कार्ड' योजना के जरिए मुफ्त सफर बंद करने की साजिश हो रही है, जिसमें महिलाओं से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं डॉ. मेहरोत्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मांग है कि दिल्ली में 'पिंक बसों' की शुरुआत होनी चाहिए, जो महिला ड्राइवर, कंडक्टर, सीसीटीवी कैमरा, पैनिक बटन और जीपीएस जैसी सुविधाओं से लैस हों. इससे न केवल महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि कामकाजी महिलाओं और छात्राओं को आत्मविश्वास भी मिलेगा. उन्होंने कहा कि, जिस तरह कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कांग्रेस सरकारों ने महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का अधिकार दिया हुआ है, वैसे ही दिल्ली की महिलाओं को भी यह सुविधा मिलनी चाहिए.

सावन शिवरात्रि पर झमाझम बारिश में भीगा दिल्ली-एनसीआर, मौसम हुआ सुहावना

नई दिल्ली। आज सावन शिवरात्रि के मौके पर दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली। सुबह से हो रही बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। बारिश के कारण कई प्रमुख सड़कें जलमग्न हो गईं। जिससे यातायात प्रभावित हुआ है, सड़कों पर वाहन रेंगते दिखे। वहीं, बारिश के बीच कांवड़ियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में कांवड़िये और शिवभक्त शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को भी गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली समेत कई इलाकों में बारिश हुई थी। दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार का दिन गर्मी से राहत लेकर आया। दो दिनों से रुके बारिश के सिलसिले और उसपर उमस के सितम से लोग बेहाल थे। मंगलवार को जब जमकर बदरा बरसे तो लोग जहां तहां इसका आनंद लेते दिखे। मौसम विभाग ने आज के लिए भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई थी। इस दौरान आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों तक बादल छाने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। 23 जुलाई को दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और हल्की बरसात होगी। अधिकतम तापमान 33 तो न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 24 से 27 जुलाई तक भी कमोबेश ऐसा ही मौसम रहेगा। इस बीच अधिकतम तापमान 36 तो वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दिल्ली में दो दिन बाद मंगलवार को बरसे बादलों से एक तरफ दिल्लीवालों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली तो वहीं कई जगह पानी जमा होने के कारण जाम का झाम भी झेलना पड़ा। लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर गुस्सा निकाला। बारिश के कारण कई सड़कों पर जलभराव हो गया और डामर की कई सड़कों पर गड्ढे हो गए जिससे यातायात धीमा पड़ गया। आईटीओ से ओल्ड रोहतक रोड, दिल्ली-जयपुर हाईवे (एनएच-8), महरौली-बदरपुर रोड, महरौली-गुरुग्राम रोड, पीरागढ़ी से आईएसबीटी, मधुबन चौक, दिल्ली-गाजियाबाद मार्ग और नेशनल हाईवे-9 पर कई घंटों तक भारी जाम लगा रहा। सोशल मीडिया पर एक शख्स ने बताया कि दिल्ली-गाजियाबाद सड़क पर सिर्फ एक किलोमीटर का रास्ता पार करने में उन्हें 30 मिनट से ज्यादा का समय लग गया। वहीं, एक अन्य शख्स ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को समय पर अलर्ट जारी न करने या स्थिति को संभालने के लिए कर्मियों को तैनात न करने का आरोप लगाया।

सीएम योगी की कुर्सी सुरक्षित नहीं..., कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहकर मचा दिया बवाल

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बुधवार (23 जुलाई, 2025) को मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख को कमजोर किया जा रहा है और जनता अब इसे समझने लगी है. उन्होंने चुनाव आयोग, बीजेपी की आंतरिक राजनीति, प्रधानमंत्री की विदेश नीति और उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने ये भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी सुरक्षित नहीं है. बीजेपी की संगठनात्मक स्थिति पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी अब खुद अपना अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही है. उन्होंने आगे कहा, बीजेपी का संगठन नेतृत्वविहीन हो गया है. पार्टी में ऐसा कोई चेहरा नहीं बचा जिसे सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया जा सके. उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी सुरक्षित नहीं है और पार्टी में उन्हें लेकर अंदरूनी घमासान चल रहा है. पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग निष्पक्षता की अपनी भूमिका खो चुका है. उन्होंने कहा, जब हम चुनाव आयोग से सवाल करते हैं तो जवाब बीजेपी देती है और जब हम बीजेपी से सवाल करते हैं तो जवाब चुनाव आयोग देता है.

कांग्रेस नेता ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया और कहा कि जनता अब इस खेल को समझने लगी है. उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि अब -मोटा भाई और छोटा भाई का भय खत्म हो रहा है. कांग्रेस नेता ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि यह इस्तीफा रहस्यमयी तरीके से हुआ है और उपराष्ट्रपति को देश के सामने अपने इस्तीफे की वजह स्पष्ट करनी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया, जब संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा था, तभी उपराष्ट्रपति का इस्तीफा आना संदेह पैदा करता है. क्या यह किसी योजना का हिस्सा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर खेड़ा ने आरोप लगाया, पीएम चीन और अमेरिका से डरते हैं. वे कठिन सवालों से बचते हैं और विदेशी दौरों के जरिए घरेलू मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं.

दिल्ली के निहाल विहार में उत्तम नगर जैसी वारदात, पत्नी ने पति की चाकू से गोदकर की हत्या

पश्चिमी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के उत्तम नगर में पत्नी द्वारा पति की हत्या करने जैसा मामला निहाल विहार में भी सामने आया है। यहां पत्नी ने चाकू से वार कर पति की हत्या कर दी। इससे पहले उसने पति को दवा देकर बेहोश कर दिया था। पुलिस के आने से पहले मृतक की पत्नी ने घर की सफाई कर दी थी। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार (चाकू) बरामद कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपित पत्नी फरजाना ने बताया कि वह अपने पति से नाखुश थी। पति को ऑनलाइन सट्टा खेलने की लत थी। वह भारी कर्ज में था। उसके साथ मारपीट भी करता था। दोनों का वैवाहिक जीवन भी सही नहीं था। इस बीच, उसकी पति के चचेरे भाई से नजदीकी बढ़ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की आंत में कई जगहों पर चाकू के घाव मिले हैं।

दिल्ली में स्विमिंग पूल और वॉटर स्पोर्ट्स, जलजमाव पर तंज कसते हुए आतिशी ने सीएम रेखा को किया धन्यवाद

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली एक ओर जहां भारी बारिश की चपेट में है, वहीं दूसरी ओर इस मौसम ने राजनीतिक गलियारों में भी गर्मी ला दी है.

आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने जलभराव की तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने तंज कसा कि बीजेपी ने दिल्ली को स्विमिंग पूल बना दिया है. आतिशी ने वसुंधरा एन्क्लेव का वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि खुद मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जलभराव की स्थिति भयावह है. वीडियो में सड़कों पर पानी भरा दिखाई देता है, जहां गाड़ियां पानी में आधी डूबी हुई हैं और कुछ जगहों पर बच्चे नाव चलाते नजर आ रहे हैं. उन्होंने व्यंग्य करते हुए लिखा, दिल्ली में इतने सारे स्विमिंग पूल शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बहुत-बहुत बधाई!

ड्रेनेज सिस्टम में भारी खामियां

आपने आरोप लगाया कि मामूली बारिश में ही दिल्ली की सड़कों का यह हाल दर्शाता है कि ड्रेनेज सिस्टम में भारी खामियां हैं. पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की चुप्पी यह साबित करती है कि नेतृत्व स्तर पर भी जवाबदेही का अभाव है. पार्टी ने इसे प्रशासनिक विफलता बताते हुए कहा कि दिल्लीवासियों के साथ मजाक किया जा रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के पोस्ट को लेकर दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है. मौसम विभाग ने आज 23 जुलाई को दिल्ली में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है. दिनभर बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है. अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जो सामान्य से थोड़ा कम है.

जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुनवाई के लिए पीठ गठित होगी, सतकोसिया निर्माण विवाद पर भी होगी सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह एक बेंच गठित करेगा जो जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें उन्होंने आंतरिक जांच समिति की उस रिपोर्ट को चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ उनके आवास पर नकदी मिलने के मामले में टिप्पणी की गई थी। यह मामला आज चीफ जस्टिस (सीजेआई) बी आर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच के समक्ष उठाया गया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, राकेश द्विवेदी, सिद्धार्थ लूथरा, सिद्धार्थ अग्रवाल और वकील जॉर्ज पोटन पूथिकोटे, मनीषा सिंह समेत अन्य लोग जस्टिस वर्मा की ओर से पेश हुए। उन्होंने कहा, हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की ओर से याचिका दायर की है। इसमें कुछ संविधानिक मुद्दे शामिल हैं। मैं निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द एक बेंच गठित की जाए। सीजेआई ने जवाब में कहा कि इस मामले को लेना उनके लिए उचित नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने कहा, हम इस पर विचार करेंगे और एक उपयुक्त बेंच बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में कथित अवैध निर्माण को लेकर दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। चीफ जस्टिस बी आर गवई (सीजेआई), जस्टिस के वी विश्वनाथन और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच के समक्ष वकील गौरव कुमार बंसल ने यह याचिका लगाई और आग्रह किया कि इस मामले पर सुनवाई जरूरी है। बेंच ने कहा कि वह इस याचिका पर किसी अगली तारीख को सुनवाई करेगी। बंसल ने यह भी चिंता जताई कि स्थानीय प्रशासन ने संरक्षित क्षेत्र के अंदर इको-टूरिज्म (पर्यावरण पर्यटन) के लिए निर्माण की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा, जिला कलेक्टर ने इको-टूरिज्म के लिए निर्माण की अनुमति दी है। यह कैसे हो सकता है? मैं तो बस जंगलों के लिए लड़ रहा हूं। सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा के अंगुल, कटक, नयागढ़ और बौध जिलों में फैला हुआ है। यह बाघों, हाथियों और कई संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास (हैबिटेट) है।

दिल्ली के डीयू में एबीवीपी का अनिश्चितकालीन धरना जारी, छात्र हितों पर प्रशासन की बेरुखी

नई दिल्ली। दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) और ABVP समर्थित दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र हितों को लेकर शुरू किया गया अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी है. आर्ट्स फैकल्टी में चल रहा यह धरना 24 घंटे का आंकड़ा पार कर चुका है. यह प्रदर्शन विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्र हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर कार्रवाई न करने के विरोध में किया जा रहा है. धरने की शुरुआत 21 जुलाई को 'छात्र अधिकार मार्च' के साथ हुई, जिसमें हजारों छात्रों ने भाग लिया. यह मार्च स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से शुरू होकर आर्ट्स फैकल्टी तक पहुंचा, जहां पर छात्र कल से लगातार धरने पर बैठे हैं. अभाविप ने अपनी प्रमुख मांगों में सभी पीजी पाठ्यक्रमों के लिए एक समान शुल्क (वन कोर्स-वन फी), केंद्रीकृत हॉस्टल आवंटन प्रणाली की स्थापना, दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन और उसका सक्रिय संचालन, तथा कॉलेजों में मनमानी फीस वृद्धि को वापस लेने को सम्मिलित किया. इन मांगों में से जहां एक ओर प्रशासन ने केंद्रीकृत हॉस्टल आवंटन की मांग पर प्रतिक्रिया दी है, वहीं बाकी अहम मुद्दों पर अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है. जब तक सभी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक अभाविप छात्र हित में ऐसे ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा रहेगा. अभाविप दिल्ली प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि हमें आर्ट्स फैकल्टी में बैठे 24 घंटे से अधिक हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक हमारी अधिकांश मांगों पर कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है. केंद्रीकृत हॉस्टल प्रणाली की शुरुआत जरूर एक सकारात्मक कदम है, लेकिन यह काफी नहीं है. छात्र महज प्रतीकात्मक सुधार नहीं, बल्कि ठोस बदलाव के हकदार हैं. अभाविप इस संघर्ष को आखिरी सांस तक जारी रखेगी. यह आंदोलन छात्र अधिकारों की रक्षा के लिए है, और हम तब तक नहीं रुकेंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं. अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेन्द्र सिंह सोलंकी ने भी धरनास्थल पर पहुंचकर छात्रों के साथ एकजुटता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है, लेकिन इसके छात्र आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं. अभाविप ने हमेशा छात्र संघर्षों की अगुवाई की है और यह अनिश्चितकालीन धरना हमारे इसी अडिग संकल्प का प्रतीक है. केंद्रीकृत हॉस्टल व्यवस्था जैसे सुधार स्वागत योग्य हैं, लेकिन जब तक फीस निर्धारण से लेकर ICC की प्रभावी कार्यप्रणाली जैसी समस्याओं का संपूर्ण समाधान नहीं होता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा. यह केवल विरोध नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय व्यवस्था में गरिमा, समानता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की लड़ाई है.

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज बोले, इनके भारतीयता का मतलब है 10 फीसदी लोग...

नई दिल्ली। (वेबवार्ता) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के भारतीयता वाले बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जात-पात, छूआछूत यहां है.भयंकर गरीबी यहां है. हिंदू-मुसलमान का रोज का झगड़ा है. जाति का नफरत है और दुनिया का कोई देश हमारे साथ नहीं है, मुंह से कुछ भी बोल दें. पहले अपने समाज को दुरुस्त करना होगा. पीटीआई से बातचीत में उदित राज ने कहा, इनके लिए भारतीयता क्या है? जातियों में बांटना, नफरत की दीवार खड़ी करना. आज भी दलित घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते. छूआछूत आज भी है. राष्ट्रपति तक मंदिर में नहीं जा सकती. क्या है इनकी भारतीयता. एक भी कॉर्पोरेट हाउस में दलित पिछड़ा नहीं है. कांग्रेस नेता ने कहा, इनके भारतीयता का मतलब है कि 10-5 फीसदी लोग बाकी के लोगों का शोषण करें. बाकी के शूद्र बनकर उनकी सेवा करें. भारतीय समाज में जाति के अलावा है क्या? अगर भारतीयता समाधान होता तो लोग देश छोड़कर भाग क्यों रहे हैं. 40 लाख लोग अमेरिका चले गए, कौन अमेरिकी, ब्रिटिश नागरिक यहां आकर रह रहा है. मोहन भागवत ने मंगलवार को लोगों से भारतीयता को आत्मसात करने और दुनिया को उन सभी समस्याओं का समाधान दिखाने का आह्वान किया, जिनका वह सामना कर रही है. इग्नू और अखिल भारतीय अणुव्रत न्यास की ओर से आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली में भागवत बोल रहे थे. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, उन्होंने कहा कि भौतिकवाद के कारण विश्व अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है और अब वह इनके उत्तर के लिए भारत की ओर देख रहा है, क्योंकि पिछले 2,000 वर्षों में लोगों के जीवन में खुशी और संतोष लाने के लिए पश्चिमी विचारों पर आधारित सभी प्रयास विफल हो गए हैं. मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया में विज्ञान और आर्थिक क्षेत्र में हुई सभी प्रगतियों ने विलासिता की चीजें ला दीं और लोगों का जीवन आसान बना दिया, लेकिन दुखों का अंत नहीं कर सकीं.

यमुना फिर उफान पर? दिल्ली पर मंडरा रहा खतरा! हथिनीकुंड से छोड़ा गया 54,000 क्यूसेक पानी

नई दिल्ली। (वेबवार्ता) दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर चिंता का विषय बनता जा रहा है. हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से इस मानसून में पहली बार 50,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है, जिससे राजधानी में जलस्तर बढ़ने की आशंका है. केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, कल (22 जुलाई) तड़के 1 बजे बैराज से जल प्रवाह 54,707 क्यूसेक पर पहुंच गया. आमतौर पर बैराज से छोड़ा गया पानी 48 से 50 घंटे में दिल्ली पहुंचता है, जहां पुराना रेलवे पुल इसका मुख्य निगरानी बिंदु है. मंगलवार (22 जुलाई) शाम 5 बजे तक पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर 202.24 मीटर दर्ज किया गया, जो चेतावनी स्तर 204.50 मीटर से नीचे है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जलस्तर बढ़ सकता है. यमुना एक्टिविस्ट और SANDRP सदस्य भीम सिंह रावत के अनुसार, ऊपरी यमुना बेसिन में बारिश जारी रही तो अगले कुछ दिनों में जलस्तर में और इजाफा संभव है. सोमवार रात 9 बजे के बाद से पानी का बहाव 4 घंटे तक 50,000 क्यूसेक से ऊपर रहा और फिर 2 बजे तक घटकर 48,974 क्यूसेक हो गया.2023 की जुलाई में भारी तबाही मचाने वाली बाढ़ के दौरान यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड 208.66 मीटर तक पहुंच गया था, जब हथिनीकुंड से 3.59 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था. पीटीआई के अनुसार, उस समय मयूर विहार, ITO, सलीमगढ़ बायपास और सिविल लाइंस जैसे कई इलाके जलमग्न हो गए थे और हजारों लोग विस्थापित हुए थे. हालांकि, सितंबर में हुई भारी बारिश के बावजूद, पिछले साल चेतावनी स्तर 204.50 मीटर को दिल्ली ने मामूली अंतर से पार नहीं किया था और जलस्तर 204.38 मीटर पर रुक गया था. दिल्ली सरकार की बाढ़ नियंत्रण योजना के अनुसार, जब हथिनीकुंड बैराज से 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जाता है, तभी औपचारिक रूप से पहली चेतावनी जारी होती है. तब सेक्टर-स्तरीय कंट्रोल रूम सक्रिय हो जाते हैं, नावों की तैनाती होती है और संवेदनशील इलाकों में निगरानी तेज कर दी जाती है. हालांकि फिलहाल ये स्थिति नहीं बनी है, लेकिन लगातार बारिश और बढ़ते जलप्रवाह को देखते हुए प्रशासन सतर्क है.

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का आरोप, भाजपा शासित राज्यों में बंगालियों को किया जा रहा अपमानित

नई दिल्ली। (वेबवार्ता) तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में बंगालियों का अपमान किया जा रहा है। दिल्ली में बोलते हुए, बनर्जी ने दावा किया कि बंगालियों को प्रताड़ित किया जा रहा है और उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात के कुछ लोग देश पर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। उन्होंने बंगालियों के ऐतिहासिक योगदान पर जोर देते हुए कहा कि गुजरातियों के विपरीत, बंगाली आजादी की लड़ाई में सबसे आगे थे। बनर्जी ने एएनआई से कहा कि हमने नारे लगाए हैं कि पूरे भारत में भाजपा शासित राज्यों में बंगालियों का अपमान किया जा रहा है। वे बंगालियों पर अत्याचार कर रहे हैं। वे बंगालियों को उठाकर बांग्लादेश वापस भेज रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात के कुछ लोग देश पर अपना दबदबा बनाएंगे? बंगाली हमेशा सबसे आगे रहे हैं। आजादी की लड़ाई में बंगाली थे, उस समय गुजराती नहीं थे। इस बीच, बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सहित कई मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के लगातार विरोध के बीच, बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने के तुरंत बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही फिर से शुरू होने के तुरंत बाद, विपक्षी सदस्यों द्वारा बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा करने के बाद राज्यसभा को एक मिनट के भीतर स्थगित कर दिया गया। हालांकि, विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा ने कुछ मिनट के लिए अपनी कार्यवाही रोक दी। इस दौरान, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में %राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 पेश किया। इससे पहले दिन में, दोनों सदनों को इसी तरह के व्यवधानों के कारण बैठक शुरू होने के कुछ ही देर बाद स्थगित कर दिया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी थी क्योंकि विपक्षी सदस्य बिहार में चुनाव आयोग द्वारा की जा रही एसआईआर प्रक्रिया सहित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए थे। सदन के वेल में तख्तियों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए, अध्यक्ष ने कहा, -देश आपके व्यवहार और आचरण को देख रहा है। मुझे बैनर लाने वाले सदस्यों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करनी होगी। यह सदन चर्चा और संवाद के लिए है, नारेबाजी के लिए नहीं। सदन की मर्यादा बनाए रखें,- बिरला ने निचले सदन की कार्यवाही स्थगित करने से पहले कहा।

ऑनलाइन भुगतान के मामले में भारत के यूपीआई ने अमेरिका के वीजा को पीछे छोड़ा

प्रह्लाद सबनानी ।

हाल ही के समय में भारत, विभिन्न क्षेत्रों में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नित नए रिकार्ड बना रहा है। कुछ क्षेत्रों में तो अब भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत ने बैंकिंग व्यवहारों के मामले में तो जैसे क्रांति ही ला दी है। अभी हाल ही में आर्थिक क्षेत्र में बैंकिंग व्यवहारों के मामले में भारत के यूनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) ने अमेरिका के 67 वर्ष पुराने वीजा एवं मास्टर कार्ड के पेमेंट सिस्टम को प्रतिदिन होने वाले आर्थिक व्यवहारों की संख्या के मामले में वैश्विक स्तर पर पीछे छोड़ दिया है। वैश्विक स्तर पर अब भारत विश्व का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट नेटवर्क बन गया है। भारत में वर्ष 2016 के पहले ऑनलाइन पेमेंट का मतलब होता था केवल वीजा और मास्टर कार्ड। वीजा और मास्टर कार्ड को चलाने वाली अमेरिका की ये दोनों कंपनियां पूरी दुनिया में ऑनलाइन पेमेंट का एकाधिकार रखती थीं। वीजा की शुरुआत, अमेरिका में वर्ष 1958 में हुई थी और धीमे धीमे यह कंपनी 200 से अधिक देशों में फैल गई और ऑनलाइन भुगतान के मामले में पूरे विश्व पर अपना एकाधिकार जमा लिया। वैश्विक स्तर पर इस कम्पनी को चुनौती देने के उद्देश से भारत ने वर्ष 2016 में अपना पेमेंट सिस्टम, यूपीआई के रूप में, विकसित किया और वर्ष 2025 आते आते भारत का यूपीआई सिस्टम आज पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर आ गया है। यूपीआई पेमेंट सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन बैंकिंग व्यवहार चुटकी बजाते ही हो जाते हैं। आज सब्जी वाले, चाय वाले, सहायता प्राप्त करने वाले नागरिक एवं छोटी छोटी राशि के आर्थिक व्यवहार करने वाले नागरिकों के लिए यूपीआई सिस्टम ने ऑनलाइन बैंकिंग व्यवहार करने को बहुत आसान बना दिया है। आज भारत के यूपीआई सिस्टम के माध्यम से प्रतिदिन 65 करोड़ से अधिक व्यवहार (1800 करोड़ से अधिक व्यवहार प्रति माह) हो रहे हैं जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वीजा कार्ड के माध्यम से प्रतिदिन 63.9 करोड़ व्यवहार हो रहे हैं। इस प्रकार, भारत के यूपीआई ने दैनिक व्यवहारों के मामले में 67 वर्ष पुराने अमेरिका के वीजा को पीछे छोड़ दिया है। भारत में केंद्र सरकार की यह सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है। भारत अब इस मामले में पूरी दुनिया का लीडर बन गया है। भारत ने यह उपलब्धि केवल 9 वर्षों में ही प्राप्त की है। विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भी भारत के यूपीआई सिस्टम की अत्याधिक प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह नई तकनीकी का चमत्कार है एवं यह सिस्टम अत्याधिक प्रभावशाली है। भारत का यूपीआई सिस्टम भारत को वैश्विक बैंकिंग नक्शे पर एक

अभी हाल ही में आर्थिक क्षेत्र में बैंकिंग व्यवहारों के मामले में भारत के यूनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) ने अमेरिका के 67 वर्ष पुराने वीजा एवं मास्टर कार्ड के पेमेंट सिस्टम को प्रतिदिन होने वाले आर्थिक व्यवहारों की संख्या के मामले में वैश्विक स्तर पर पीछे छोड़ दिया है। वैश्विक स्तर पर अब भारत विश्व का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट नेटवर्क बन गया है। भारत में वर्ष 2016 के पहले ऑनलाइन पेमेंट का मतलब होता था केवल वीजा और मास्टर कार्ड। वीजा और मास्टर कार्ड को चलाने वाली अमेरिका की ये दोनों कंपनिया पूरी दुनिया में ऑनलाइन पेमेंट का एकाधिकार रखती थीं। वीजा की शुरुआत, अमेरिका में वर्ष 1958 में हुई थी और धीमे धीमे यह कंपनी 200 से अधिक देशों में फैल गई और ऑनलाइन भुगतान के मामले में पूरे विश्व पर अपना एकाधिकार जमा लिया।

बहुत बड़ी शक्ति बना सकता है। भारत में यूपीआई की सफलता की नींव दरअसल केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई कई आर्थिक योजनाओं के माध्यम से पड़ी है। समस्त नागरिकों के आधार कार्ड बनाने के पश्चात जब आधार कार्ड को नागरिकों के बैंक खातों से जोड़ा गया और केंद्र सरकार द्वारा देश के गरीब वर्ग की सहायता के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता राशि को सीधे ही नागरिकों के बैंक खातों में जमा किया जाने लगा तब एक सुदृढ़ पेमेंट सिस्टम की आवश्यकता महसूस हुई और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के रूप में यूपीआई का जन्म वर्ष 2016 में हुआ। यूपीआई को आधार कार्ड एवं प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बैंकों में खोले गए खातों से जोड़ दिया गया। नागरिकों के मोबाइल क्रमांक और आधार कार्ड को बैंक खातों से जोड़कर यूपीआई सिस्टम के माध्यम से आर्थिक एवं लेन-देन व्यवहारों को आसान बना दिया गया। भारत में आज लगभग 80 प्रतिशत युवा एवं बुजुर्ग जनसंख्या का विभिन्न बैंकों में खाता खोला जा चुका है। यूपीआई के माध्यम से केवल कुछ ही मिनटों में एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में राशि का अंतरण किया जा सकता है। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के रूप में यूपीआई के आने के बाद तो अब भारत के नागरिक एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड को भी भूलने लगे हैं। भारत से बाहर अन्य देशों में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिक भी अपनी बचत को यूपीआई के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में ऑनलाइन राशि का अंतरण चंद मिनटों में कर सकते हैं। पूर्व में, बैंकिंग चेनल के माध्यम से एक देश के बैंक खाते से दूसरे देश के बैंक खाते में राशि का अंतरण करने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता था तथा विदेशी बैंकों द्वारा इस प्रकार के अंतरण राशि पर खर्च भी वसूला जाता है। अब यूपीआई के माध्यम से कुछ ही मिनटों में राशि एक देश के बैंक खाते से दूसरे देश के बैंक खाते में अंतरित हो जाती है। इससे भारतीय रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण भी हो रहा है। विश्व के अन्य देशों में पढ़ाई के लिए गए छात्रों को अपने खर्च चलाने एवं विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में फीस की राशि यूपीआई सिस्टम से जमा करने में बहुत आसानी होगी। जिस भी देश में भारतीय मूल के नागरिकों की संख्या अधिक है उन देशों में भारत के यूपीआई सिस्टम को लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज 13,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि इन देशों में निवास कर रहे भारतीय मूल के नागरिकों द्वारा प्रतिवर्ष भारत में भेजी जा रही है। वैश्विक स्तर पर भारत के यूपीआई सिस्टम की स्वीकार्यता बढ़ने से अमेरिकी डॉलर पर भारत की निर्भरता भी कम होगी, इससे भारतीय रुपए की मांग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी और डीडोलराईजेशन की प्रक्रिया तेज होगी। भारत ने यूपीआई के प्रतिदिन होने वाले व्यवहारों की संख्या के मामले में आज अमेरिका, चीन एवं पूरे यूरोप को पीछे छोड़ दिया है। वर्तमान में भारत के यूपीआई सिस्टम का विश्व के 7 देशों यथा यूनाइटेड अरब अमीरात, फ्रान्स, ओमान, मारीशस, श्रीलंका, भूटान एवं नेपाल में उपयोग हो रहा है। इन देशों में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिक यूपीआई के माध्यम से सीधे ही भारत के साथ आर्थिक व्यवहार कर रहे हैं। दक्षिणपूर्वीय देशों यथा मलेशिया, थाईलैंड, फिलिपीन्स, वियतनाम, सिंगापुर, कम्बोडिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ताईवान एवं हांगकांग आदि भी भारत के यूपीआई सिस्टम के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम, आस्ट्रेलिया एवं यूरोपीयन देशों ने भी भारत के यूपीआई सिस्टम को अपने देश में लागू करने की इच्छा जताई है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की घाना एवं नामीबिया यात्रा के दौरान इन दोनों देशों ने भारत के यूपीआई सिस्टम को अपने देश में शुरू करने के लिए भारत से निवेदन किया है। पूरे विश्व में अब कई देशों का विश्वास भारत के यूपीआई सिस्टम पर बढ़ रहा है और यदि ये देश भारत के यूपीआई सिस्टम को अपने देश में लागू कर देते हैं तो इससे भारत में विदेशी निवेश की राशि में भी तेज गति से वृद्धि होने की सम्भावना बढ़ जाएगी।

चुनाव आयोग और आधार कार्ड

चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय की यह सलाह मानने से इन्कार कर दिया है कि बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण व सत्यापन में आधार कार्ड, राशन कार्ड व वोटर पहचान पत्र को भी एक पैमाना माना जाये। आयोग ने न्यायालय के निर्देशानुसार 21 जुलाई को एक शपथ पत्र दाखिल कर यह कहा है कि वह इन तीनों दस्तावेजों में से किसी एक को भी जायज मतदाता होने का आधार नहीं मान सकता है क्योंकि इन तीनों में से कोई भी दस्तावेज या प्रपत्र किसी मतदाता के भारतीय नागरिक होने का प्रमाण नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा है कि आधार कार्ड भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है हालांकि यह नागरिकों के अन्य दस्तावेज तैयार कराने में काम आता है। चुनाव आयोग ने विगत दिनों 11 ऐसे प्रपत्रों की सूची जारी की थी जिन्हें दिखाने पर ही किसी भी मतदाता के जायज होने का सबूत मिलता। इन 11 प्रपत्रों में उपरोक्त तीन प्रपत्र शामिल नहीं थे। इसके बाद बिहार की राजनीति में भूचाल जैसा आ गया था और सभी विपक्षी राजनैतिक दल चुनाव आयोग के इस फैसले की आलोचना कर रहे थे। इसके विरोध में बहुत से भाजपा विरोधी राजनैतिक दलों व नेताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं भी दायर की थीं। उन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ही सर्वोच्च न्यायालय ने आयोग को सलाह दी थी कि वह आधार कार्ड, राशन कार्ड व वोटर पहचान पत्र को भी 11 दस्तावेजों के साथ जोड़ सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव आयोग मतदाता सूचियों का जो गहन पुनरीक्षण कर रहा है उसमें सभी फर्जी मतदाताओं के बाहर होने का रास्ता खुलता है। परन्तु इसके साथ ही कुछ ऐसे मतदाता भी हैं जिनके जायज होने के बावजूद सूची से बाहर होने का दरवाजा भी खुल सकता है क्योंकि चुनाव आयोग 1987 से 2003 के बीच पैदा हुए नये मतदाताओं का जन्म प्रमाणपत्र भी मांग रहा है। चुनाव आयोग ने साथ ही यह भी घोषणा की थी कि जिन मतदाताओं के नाम 2003 की पुनरीक्षण सूची में थे उन्हें चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं है मगर आयोग द्वारा जारी पुनरीक्षण के लिए जारी फार्म को उन्हें भी भरना होगा। आयोग ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि यह उसका संवैधानिक दायित्व है कि मतदाता आवश्यक रूप से भारत का नागरिक हो मगर मतदाता सूची में उसका नाम न आने से उसकी नागरिकता का अधिकार छिनता भी नहीं है। भारत में नागरिकता की पहचान का कार्य गृह मन्त्रालय करता है।

यह कार्य चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। विगत 10 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने विपक्षी दलों द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा था कि वह बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के काम को रोक नहीं रहा है बल्कि आधार कार्ड, राशन कार्ड व वोटर पहचान पत्र को भी शामिल करने का सुझाव दे रहा है। जबकि विपक्षी दल मांग कर रहे थे कि पुनरीक्षण के काम पर तुरन्त रोक लगाई जाये। चुनाव आयोग का कहना है कि जहां तक राशन कार्ड का सवाल है तो इनके लाखों की संख्या में बोगस या फर्जी तरीके से जारी होने की बात स्वयं सरकारों की तरफ से कही गई है। इस बारे में आयोग ने विगत 7 मार्च को केन्द्र सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कि देश में लाखों की संख्या में बोगस राशन कार्ड मौजूद हैं। अतः राशन कार्ड को भी जायज नागरिकता का प्रमाणपत्र नहीं माना जा सकता है और जहां तक वोटर पहचान पत्र का सवाल है तो वे तब जारी परिपाटी के अनुसार ही बनाये जाते हैं और यह वर्तमान में जारी सूची के ही अंग हैं जबकि इनके सत्यापन का कार्य अब जारी है। अतः इन्हें भी प्रमाण नहीं माना जा सकता। पिछले बीस साल से बिहार में मतदाता सूचियों के सत्यापन या पुनरीक्षण का काम नहीं हुआ है। अतः यह कार्य करना अब बहुत जरूरी है। आयोग के अनुसार उसने जो 11 प्रपत्रों की सूची जारी की है वह कोई बहुत बड़ी मुसीबत की चीज नहीं है बल्कि केवल सांकेतिक है जिससे किसी भी मतदाता के जायज होने का सबूत मिल सके। आयोग के आदेश के अनुसार बिहार के सभी 7.8 करोड़ मतदाताओं को नया फार्म भरना होगा जिससे सभी की पहचान हो सके। इनमें से केवल उन्हीं मतदाताओं को 11 प्रपत्रों में से एक देने के लिए कहा गया है जिनके नाम 2023 के बाद मतदाता सूची में जुड़े हैं। गौर से देखा जाये तो चुनाव आयोग की यह कसरत व्यर्थ भी नहीं है क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसी शिकायतें मिलती रहती हैं कि मतदाता सूचियों में फर्जी नामों को रखा गया है और एक मतदाता के अलग-अलग पतों से दो-दो वोटर पहचान पत्र भी हैं। चुनाव आयोग के नये निर्देशों के अनुसार यह जिम्मेदारी अब नागरिक पर आ गई है कि वह अपनी नागरिकता साबित करे। चुनाव आयोग के अनुसार इसमें कोई गलत बात नहीं है क्योंकि भारत में जन्मे लोगों की नागरिकता का जहां तक सवाल है तो उन्हें ही सिद्ध करना होगा कि उनका जन्म भारत में हुआ है और इसके लिए उन्हें जन्म तिथि व स्थान का प्रमाण देना होगा जिससे उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ सके। यह प्रबन्ध ऐसे नये मतदाताओं पर ज्यादा लागू होता है जो हाल ही में 18 वर्ष के हुए हैं। कुल मिलाकर चुनाव आयोग की कवायद की आंख मींच कर आलोचना भी नहीं की जा सकती है। मगर यह भी सत्य है कि निर्वाचन आयोग बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण जल्दबाजी में करा रहा है।

भारतीय मुसलमानों को कट्टरपंथ का विरोध क्यों करना चाहिए?

भारतीय मुसलमानों के बारे में एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जब पूरी दुनिया, खासकर पश्चिम एशिया, 'इस्लामी कट्टरपंथ' की चपेट में है, तब भी यह समुदाय अंतर्राष्ट्रीय कट्टरपंथ में सक्रिय रूप से शामिल नहीं रहा है, इस प्रकार इस कलंक से बेदाग रहा है। कुछ कट्टरपंथियों को छोड़कर, भारत से किसी ने भी उग्रवादियों की ओर से युद्ध लड़ने के लिए सीमा पार नहीं की, जबकि युवाओं को लुभाने के लिए नियमित रूप से ऑनलाइन अभियान चलाये जाते हैं। इसी तरह, 1980 के दशक में हमारे पड़ोसी अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद छेड़ा गया था, जहां धर्म-समर्थक की भीड़ जमा हुई थी और बाद में इन लोगों ने दुनिया के संवेदनशील क्षेत्रों को जहर फैलाने के लिए अपना ठिकाना बनाया। लेकिन भारत के 18 करोड़ मुसलमानों में से कोई भी इस 'पवित्र युद्ध' में शामिल नहीं हुआ था। भारत के कुछ मौलवी हलकों में इस जिहाद का महिमामंडन करने के बावजूद ऐसा हुआ। जब अल-कायदा दुनिया भर से भर्ती कर रहा था, तब भारतीय मुसलमानों ने उसके आह्वान और विचारधारा का पुरजोर विरोध किया। बाद में, जब इसका सबसे खतरनाक रूप -इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक (आईएसआईएस), या दाएश-सामने आया और भोले-भाले युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक जबरदस्त मीडिया अभियान चलाया, तो उसके कार्यकर्ताओं में बहुत कम मुस्लिम नाम दिखाई दिए और खाड़ी देशों से अपहरण के बाद उन्हें समूह में शामिल होने के लिए मजबूर भी किया गया। भारतीय मुसलमानों के लिए उग्रवादी कट्टरपंथ के खिलाफ एक सुरक्षात्मक धुरी के रूप में किस चीज़ ने काम किया है? यह भारत में गहरी जड़ें जमाए हुए समन्वयवादी लोकाचार है जो न केवल भारतीय समाज में मौजूद है, बल्कि देश के संविधान में भी निहित है। निरंतर चुनौतियों के बावजूद, देश एक मजबूत लोकतंत्र रहा है। साथ ही, भारतीय इस्लाम सूफ़ी परंपरा की नींव पर बना है, जो अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु दृष्टिकोण और एक समावेशी जीवन शैली में विश्वास करती है। यह उग्रवाद के सिद्धांत के खिलाफ एक टिकाऊ आधार के रूप में कार्य करती है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय मुसलमान खतरे से बाहर हैं। जैसे-जैसे भारत के भीतर और विदेशों की चुनौतियां दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, वैसे-वैसे यह संभावना भी बढ़ती जा रही है कि उग्रवाद और कट्टरपंथी विचार मुसलमानों, खासकर युवाओं में पैठ बना सकते हैं। ऐसा क्षितिज पर दिखाई दे रहा है। गैरकानूनी गतिविधियोंकथाम अधिनियम (यूएपीए) की अनुसूची 1 में प्रतिबंधित 36 आतंकवादी समूहों में से 14 इस्लामी हैं। इनमें पाकिस्तानी समूह और कश्मीर स्थित स्थानीय समूह शामिल हैं। खतरे की घंटी बज रही है और जागरूक भारतीय मुसलमानों का यह दायित्व है कि वे भारतीय परिवेश में कट्टरपंथी प्रवृत्तियां,जहां भी और जिस भी रूप में दिखाई दें, उनका मुकाबला करें। वास्तव में, उन्हें कट्टरवाद-विरोधी आख्यान तैयार करके कट्टरवाद के विरुद्ध एक सक्रिय मोर्चा भी खोलना होगा।

सम्पादकीय...

स्वास्थ्य की चिंता

जिस देश में कुरकुरे समोसे और चाशनी में डूबी जलेबी मॉनसून की बारिश और क्रिकेट के जुनून की तरह हमारे जीवन का हिस्सा हों, वहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की स्ट्रीट फूड संस्कृति पर जैसे ग्रेनेड से हमला किया है। स्वास्थ्य सजगता के नाम पर मंत्रालय के एक दिशा निर्देश ने, जिसमें हमारे पसंदीदा नाश्ते की परंपरा को खत्म कर देने की धमकी है, देश को गुस्से, व्यंग्य और प्रतिरोध से भर दिया है। पिछले महीने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने एक चिट्ठी के जरिये तूफान खड़ा कर दिया, जिसमें सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया गया कि वे कैफेटेरिया और सार्वजनिक गलियारों में 'ऑयल और शुगर बोर्ड' लगाएं, जिनमें समोसे, जलेबी, वड़ा पाव, कचौरी, यहां तक कि पिज्जा और बर्गर में भी छिपी हुई वसा और चीनी की मात्रा के बारे में बताया गया हो। बाद में हालांकि मंत्रालय ने सफाई दी कि उसका इरादा किसी खास उत्पाद को निशाना बनाने का नहीं था, लेकिन जो नुकसान होना था, वह हो चुका था। बताया गया कि देश में बढ़ रहे मोटापे और गैरसंक्रामी बीमारियों के कारण यह दिशा निर्देश जारी किया गया। 'द लांसेट' जैसी प्रतिष्ठित चिकित्सा विज्ञान पत्रिका का आकलन है कि 2050 तक भारत में ज्यादा वजन वाले लोगों का आंकड़ा बढ़कर 44.9 करोड़ हो जायेगा, पर अस्पष्ट तथा स्वास्थ्य के पश्चिमी नजरिये पर आधारित इस दिशा निर्देश का उल्टा असर हुआ और सांस्कृतिक विरासत पर नौकरशाही के दखल की बहस शुरू हो गयी, समोसे और जलेबी को निशाना बनाने की कोशिश क्यों? जब अल्ट्रा-प्रोसेस्ड यानी औद्योगिक प्रक्रियाओं से गुजरे चिप्स, कोला और कुकीज जैसे स्वास्थ्य के असली दुश्मन हर सुपर मार्केट में मौजूद है, तब समोसे और जलेबी को निशाना बनाने की कोशिश क्यों? दिशा निर्देश में तेल और चीनी के अत्यधिक इस्तेमाल वाले और भी खाद्य पदार्थों का जिक्र है, जैसे-पकौड़े, गुलाब जामुन, केले के चिप्स आदि। इन सबको इनके पश्चिमी समकक्षों की तरह खतरनाक बताया गया है, लेकिन भारतीय खाद्य पदार्थों को सिर्फ कैलोरी के आईने में नहीं आंका जा सकता. दाल और घी में सेंकी गयी बाटियों वाले मशहूर राजस्थानी व्यंजन दाल-बाटी चूरमा, लूची (पूड़ी)-आलूर दम (दम आलू), रसगुल्ले और संदेश जैसे बंगाली व्यंजन या मुगलई बिरयानी और कोरमा हमारी सांस्कृतिक विरासत है। ये भारत की पहचान के प्रतीक हैं और इनमें से हर व्यंजन में हमारे स्वास्थ्य की बेहतरी के गुण पाये जाते हैं-हल्दी और जीरा जैसे मसाले हमारी पाचन क्षमता बढ़ाते हैं, तो समूह भोज के आयोजन हमें मानसिक रूप से स्वस्थ और समृद्ध करते हैं। इन व्यंजनों पर चेतावनी जारी करना सदियों पुरानी ज्ञान परंपरा पर आघात और भारतीय भोजन की समृद्ध विरासत को मिटाने जैसा है। हमारे यहां से पहले दूसरे देशों में ऐसे ही दिशा निर्देश जारी किये गये। बढ़ते मोटापे को देखते हुए मेक्सिको में सोडा और चिप्स जैसे हाई शुगर, हाई फैट उत्पादों पर 2020 से ही चेतावनी जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है। ब्रिटेन अधिक चीनी वाले पेय पदार्थों पर टैक्स अधिक लगाने के बारे में सोच रहा है, तो सिंगापुर में हेल्थ प्रमोशन बोर्ड अपने नागरिकों को तेल में डूबे फ्राइड नूडल से दूर रहने की हिदायत देता है। विदेशों में जारी इन चेतावनियों में एक बात समान है। इन सबमें सोडा, फाई, डोनट्स जैसे प्रसंस्कृत उत्पादों को निशाना बनाया गया है. ये सब खूबसूरत पैकेजिंग में कॉरपोरेट दिग्गजों द्वारा बेचे जाते हैं, लेकिन भारत में स्ट्रीट फूड्स को निशाना बनाता स्वास्थ्य मंत्रालय का दिशानिर्देश धोखे जैसा लगता है-मानो सड़क किनारे के दुकानदार द्वारा खूबसूरती से लपेटे गये समोसे बिग मैक (मैकडोनाल्ड के हैम्बर्गर) जितने नुकसानदेह हों। बर्गर (471 ग्राम के पिज्जा में 1377 कैलोरी), फ्रेंच फ्राई (117 ग्राम में 342 कैलोरी) और चॉकलेट पेस्ट्री (गुलाब जामुन के बराबर वजन की पेस्ट्री में 32 ग्राम चीनी) कोई कम नुकसानदेह नहीं है, लेकिन इन्हें निशाना नहीं बनाया गया है, क्यों? शायद इसलिए कि करी, डोसा, इडली, पराठा और बिरयानी जैसे भारतीय व्यंजनों ने लंदन के करी हाउस से न्यूयॉर्क के डोसे की दुकानों तक में अपनी प्रसिद्धि का झंडा लहराया है और वहां किसी को इससे परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश पर सोशल मीडिया पर व्यंग्यात्मक प्रतिक्रियाएं देखने लायक हैं, एक्स पर एक ने लिखा, 'भारत में समोसे और जलेबी पर सिगरेट जैसा हेल्थ अलर्ट जारी किया गया' दूसरे व्यक्ति ने इससे जुड़ी विडंबना को व्यक्त करते हुए लिखा, 'समोसे और जलेबी पश्चिमी दुनिया में लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन अपने घर में इन्हें निशाना बनाया जा रहा है।' एक और टिप्पणी है, 'समोसा और जलेबी आप बेहतर स्वास्थ्य के लिए नहीं खाते, इनका सेवन आनंद की प्राप्ति के लिए करते हैं,' समोसा और जलेबी केवल खाद्य पदार्थ नहीं है ये दिवाली की शाम के आनंद हैं, ईद की मिठास हैं, बरसाती दिनों में चाय के साथ की गर्माहट हैं, इन्हें निशाना बनाना भारत की आत्मा को निशाना बनाना है। एम्स, नागपुर से निर्देशित सरकारी दिशा निर्देश में कैलोरी को महत्व देने के पश्चिमी विमर्श की बू आती है, जबकि इसमें तले हुए और मसालेदार भारतीय व्यंजनों के महत्व की अनदेखी की गयी है। एक विशेषज्ञ ने इंस्टाग्राम पर इस दिशा निर्देश की धज्जियां उड़ाते हुए ठीक ही लिखा, 'अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हमारे स्वास्थ्य के असल दुश्मन हैं' समोसा और जलेबी ने आपका क्या बिगाड़ा है?' सांस्कृतिक विरासत और कॉरपोरेट कंपनियों के जंक फूड्स में फर्क न कर पाने की स्वास्थ्य मंत्रालय की विफलता बताती है कि विदेश में पढ़े-लिखे हमारे सरकारी बाबुओं को सामान्य भारतीयों के जीवन की जानकारी नहीं है। तब यह दिशा निर्देश और भी निराश करता है, जब हम पाते हैं कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर भारतीयों का प्रदर्शन संतोषजनक है। भारतीयों की जीवन प्रत्याशा वर्ष 2000 के 63.7 साल से बढ़कर 2024 में 76 वर्ष हो गयी, इसकी तुलना नाइजीरिया (54.7 वर्ष) और अमेरिका (77.5 वर्ष) से करें, जहां मोटापा और नशीले दवाओं का बढ़ता चलन संकट का रूप ले चुके हैं, भारत में लोग योग को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और घर के खाने को तरजीह देते हैं। स्वास्थ्य के प्रति भारतीयों की इस समर्पण भावना के पीछे सरकारी पहल कम और लोगों, समाजों की सजगता ज्यादा है। इस देश के लोग जानते हैं कि कब जलेबी का मजा लेना है और कब मिल-जुलकर समोसे खाने हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश ने सजगता पैदा करने की जगह भ्रम ही ज्यादा फैलाया है। चेतावनी बोर्ड लगाने के बजाय अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स पर अंकुश लगाना तथा लोगों को शांति से अपने पारंपरिक खाद्य पदार्थों का आनंद लेने देना अधिक जरूरी है।

एसआईआर की आंच से तपने लगा पश्चिम बंगाल

डॉ. आशीष वशिष्ठ ।

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है। विपक्ष लगातार एसआईआर का विरोध कर रहा है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में भी एसआईआर के विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। एसआईआर का मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में एसआईआर पर रोक नहीं लगाई, लेकिन अभियान की टाइमिंग को लेकर प्रश्न अवश्य उठाए हैं। भारत निर्वाचन आयोग बिहार के बाद, चुनाव आयोग इस वर्ष के अंत तक 2026 में चुनाव होने वाले पांच राज्यों में मतदाता सूचियों की इसी प्रकार की समीक्षा करेगा। असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले वर्ष मई-जून में समाप्त हो रहा है। ध्यान रहे पश्चिम बंगाल और असम दोनों ही राज्यों में एनआरसी बड़ा मुद्दा है क्योंकि इन राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों और शरणार्थियों की बड़ी संख्या है। पश्चिम बंगाल में जहां तृणमूल कांग्रेस एसआईआर को लेकर बेचैन है तो वहीं कांग्रेस असम को लेकर चिंतित है। गैर भाजपाशासित कई राज्यों से विरोध की आवाज उठने लगी है। हालांकि विरोध का सबसे ऊंचा स्वर पश्चिम बंगाल से सुनाई दे रहा है, जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे। बीती 21 जुलाई को कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस रैली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा बंगाल में एसआईआर जैसी कवायद करने की योजना बना रही है, इसे कभी अनुमति नहीं दी जाएगी। वास्तव में, ममता के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी है। एसआईआर कराना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र का विषय है। सब कुछ जानते बूझते हुए भी ममता एसआईआर को लेकर भाजपा पर राजनीतिक बाण चला रही है। भला एसआईआर करवाने या न करवाने से भाजपा का क्या संबंध? सोचिए, पश्चिम बंगाल में एसआईआर अभी शुरू भी नहीं हुआ, और ममता बनर्जी ने इसके विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। इसी से तृणमूल कांग्रेस की बेचैनी को समझा जा सकता है। ममता बनर्जी का सार्वजनिक मंच से यह कहना कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीधे तौर पर चुनाव आयोग को धमकी के साथ संविधान और संवैधानिक संस्था का अपमान भी है। संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के मन में आदर का भाव बचा ही नहीं है। सीबीआई के अधिकारियों को बंधक बनाने से लेकर ईडी के अधिकारियों पर प्राणघातक हमले में प्रदेश सरकार और तृणमूल कांग्रेस की भूमिका जगजाहिर है। अभी हाल ही में संसद द्वारा पारित वक्फ बिल के विरोध में ममता ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगी। भला कोई संविधान के तहत निर्वाचित सरकार और मुख्यमंत्री ऐसे कैसे गैरजिम्मेदाराना संविधान विरोधी बयानबाजी कर सकता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने नियम कानून और संविधान को शायद खूंटी पर टांग रखा है। ममता बनर्जी एसआईआर को एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर से भी ज्यादा खतरनाक बता चुकी हैं। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नेता डेरेक ओ ब्रायन ने बीती 28 जून को कहा कि चुनाव आयोग द्वारा घोषित मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण -पिछले दरवाजे से एनआरसी लाने का एक भयावह कदम है।' संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने संसद में प्रदर्शन किया है। तृणमूल कांग्रेस के अलावा कांग्रेस, राजद, सपा और विपक्ष के अन्य दल इस विरोध में शामिल हैं। राजनीतिक हलकों में इस बात की जोरों से चर्चा है कि बिहार के बाद मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की बारी पश्चिम बंगाल की होगी। तभी पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस बहुत बेचैन है। तृणमूल कांग्रेस को यह चिंता सता रही है कि अगर चुनाव आयोग ने चुनिंदा विधानसभा क्षेत्रों में टारगेट करके मतदाताओं के नाम काटे तो उसका फायदा भाजपा को होगा। पश्चिम बंगाल में 30 फीसदी मुस्लिम आबादी है, जिसके बारे में भाजपा आरोप लगाती है कि इनमें बड़ी संख्या बांग्लादेशी और रोहिंग्या की है। इनका वोट एकमुश्त तृणमूल को जाता है। हर क्षेत्र में 10 से 20 हजार नाम अगर कट जाते हैं तो तृणमूल को उसका बड़ा नुकसान होगा। हालांकि बिहार से उलट पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता ज्यादा जागरूक और सक्रिय हैं। वे आसानी से नाम नहीं कटने देंगे। पिछले कई महीनों से वे खुद घर घर जाकर सब चेक कर रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि पिछले 14 वर्षों में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को मतदाता सूची में व्यवस्थित रूप से घुसपैठ कराई है। बीते मार्च पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को ऑडिट और मतदाता सूची संशोधन की जरूरत से अवगत कराते हुए बताया था कि पश्चिम बंगाल में 13 लाख से अधिक फर्जी या डुप्लीकेट मतदाता हैं। बीते जून को भाजपा ने दावा किया कि बंगलादेश से जुड़े कोटा सुधार आंदोलन के नेता न्यूटन दास का नाम काकद्वीप विधानसभा इलाके के वोटर लिस्ट में है। तृणमूल ने आरोपों से इनकार किया है। बीते दिनों मालदा जिले के गाजोल के एक गांव में ऐसा मामला सामने आया है, जहां इलाके में एक भी अल्पसंख्यक व्यक्ति नहीं रहता, वहां दो अपरिचित और कथित अल्पसंख्यक वोटरों के नाम नये मतदाता सूची में शामिल पाये गये हैं। इसे लेकर भाजपा विधायक चिन्मय देव बर्मन ने अवैध घुसपैठ और फर्जी वोटर जोड़ने का आरोप लगाया है। बीती जून को सिलीगुड़ी में फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने किया था। राज्य में अलग-अलग क्षेत्रों से फर्जी वोटर मामले सामने आने के कारण राजनीतिक माहौल और गर्माया हुआ है। ममता बनर्जी ने 'फेक वोटर' की पहचान के लिए एक समिति भी बनाई है। जानकार मानते हैं कि दिल्ली की जीत के बाद भाजपा की नजर 2026 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को पछाड़ने पर है। दिल्ली चुनाव में मिली जीत से भाजपा का आत्मविश्वास बढ़ा है और वो ज्यादा मजबूती से ममता बनर्जी को चुनौती देने की कोशिश करेगी। ममता बनर्जी भी जमीनी सच्चाई और आने वाले राजनीतिक खतरों को बखूबी भांप रही हैं। इसलिये उन्होंने अभी से विरोध का स्वर ऊंचा करना शुरू कर दिया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इंडी गठबंधन के नेता संविधान के सम्मान और रक्षा की बात करते हैं। लेकिन उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का भेद है। वो कदम कदम पर संविधान, संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र की परंपराओं का अनादर करते दिखाई देते हैं। एक तरफ, विपक्ष चुनाव आयोग पर भाजपा से मिलीभगत के आरोप लगाता है। वहीं दूसरी तरफ, जब चुनाव आयोग मतदाता सूची की त्रुटियों को दूर कर साफ सुथरी सूची बनाने का अभियान चलाता है, तो उसका विरोध करने लगता है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कनन ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पश्चिमत्तना एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/570, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, फोन : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादस्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/08862)

नई दिल्ली दा (आकाश शक्य)नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ मिलकर बिहार में चल रही विशेष व्यापक पुनरीक्षण (स्क्र) प्रक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छाया- आकाश शक्य

जयपुर गोल्डन अस्पताल बना ठगी का अड्डा।

नई दिल्ली (कार्यालय संवाददाता) को बताया सरकार से सस्ते में जमीन और ग्रांट लेकर बनाया गया जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल स्वास्थ्य सेवाएं देने के नाम पर ठगी का अड्डा बनता जा रहा है उन डॉक्टर की मदद से जोकि मरीज , गरीबों और देश की सेवा करने के नाम पर बड़ी-बड़ी डिग्रियां हासिल करके आए है।

जयपुर गोल्डन अस्पताल में मैं हो रही इस तरह ठगी का नमूना पिछले दिनों तब देखने को मिला जब एक, मरीज को इलाज करने के लिए आजादपुर जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में अपनी पत्नि को देखने के लिए ओ पी डी, डॉक्टर गरिमा गुप्ता ने इलाज के नाम पर बड़े-बड़े टेस्ट लिखकर दिये और मरीज देखने के नाम पर एक तगड़ी रकम ऐंठ ली इस विषय में पेशेंट ने अपने अधिकार के तहत जब स्पष्टीकरण मांगा तो डॉक्टर गरिमा गुप्ता ने उनसे मेरा कहा की डॉक्टरी मेरा बिजनेस है और इस बिजनेस से मैं ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाना चाहती हूं इतना कहकर उन्होंने पेशेंट से अपशब्द बोलते हुए उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया इस विषय में मरीज ने तुरंत ही जयपुर गोल्डन की एम एस, डॉ सुनीता से संपर्क किया तो उन्होंने यह माना कि डॉक्टर गरिमा गुप्ता इस तरह की बदतमीजी करने के लिए मशहूर है और उनका इसलिए कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि वे अस्पताल को तगड़ी रकम कमीशन के रूप में कमा कर दे रही है, परेशान होकर मरीज ने दिल्ली सरकार और केंद्रीय सरकार के स्वास्थ्य विभाग को लिखा है और न्याय की मांग करते हुए जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल और उसमें बैठने वाले डॉक्टर पर लगाम कसने की अपील की है उल्लेखनीय है कि इस तरह की एक घटना कुछ समय पहले भी जयपुर गोल्डन अस्पताल में घटी थी जिसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग से की गई तो जयपुर गोल्डन अस्पताल की तरफ से माफी मांग कर और संबंधित मरीज को अपना रुतबा दिखाकर शांत कर दिया गया था, शिकायत हो चुकी है अब देखना यह है कि दिल्ली सरकार और केंद्रीय सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से करवाई कितनी जल्दी और कितनी तत्परता से होती है।

श्रावण मास के पवित्र अवसर कांवड़ियों के जलपान एवं विश्राम की नगर पालिका अध्यक्ष ने की व्यवस्था

पडरौना, कुशीनगर ।

नगर के जूनियर हाइस्कूल प्रांगण, पडरौना में नगरपालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल द्वारा बाबा के इन देवतुल्य कांवड़ियों के लिए विशेष जलपान एवं विश्राम व्यवस्था की गई। शीतल जल, ताजगी भरे फल, पौष्टिक नाश्ते और आराम के लिए समुचित व्यवस्था कर, कांवड़ियों को थोड़ी राहत देने का प्रयास किया गया। पालिकाध्यक्ष श्री जायसवाल ने जानकारी के तहत बताया कि माँ नारायणी का पवित्र जल भरकर बाबा कुबेरनाथ को जलार्पण करने वाले देवतुल्य कांवड़ियों की सेवा का यह कार्य विगत 25 वर्षों से किया जा रहा है। यह न सिर्फ एक सेवा है, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर क्षण है, जहाँ शिवभक्तों की थकान को हरने और उनके उत्साह को बढ़ाने का छोटा-सा प्रयास किया जाता है। इस अवसर पर क्षेत्रीय जनता ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया और कांवड़ियों का गुलाल, फूलों व जयकारों से स्वागत किया। नपाध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष जायसवाल ने स्वयं मौजूद रहकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और कांवड़ियों की सेवा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान उनके साथ सभासद गण अनिल जायसवाल श्याम साहा उत्तम चौहान अविनाश सिंह अरुण कुशवाहा मोनू कुशवाहा राजेश जायसवाल बृजेश शर्मा अरुण सिंह कन्हैया चौरसिया अजय जायसवाल सोनू शर्मा छोटू शाह अशोक जायसवाल गौरव रौनियार विनय मद्धेशिया नीरज मिश्रा आलोक विश्वकर्मा अमित तिवारी संतोष चौहान रामु पांडेय सखी मित्र पिंटू साह सुनील साहा अभय मारोदीया संजय साहा भोला साहा अजय शर्मा आनंद रावत अनूप गौड़ आकाश वर्मा भगत यादव भोलू यादव विक्की सिंह प्रमोद मद्धेशिया रवि शर्मा श्यामू शर्मा मोहन सिंह काशी राजभर सहित अन्य उपस्थित रहे।

छितौनी में बिजली कटौती से बेहाल ग्रामीण

दिनभर बिजली गुल, पानी की किल्लत; बच्चे-बुजुर्ग और व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर।

नगर पंचायत छितौनी भीषण गर्मी, उमस और बिजली की बेतहाशा कटौती की तिहरी मार झेल रहा है, जिससे यहां का जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। आसमान से बरसती आग और चिपचिपी उमस ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, और ऐसे में बिजली की आंख-मिचौली व अघोषित बेतहाशा विद्युत कटौती ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया है।

गर्मी और उमस का प्रकोप

छितौनी में दोपहर के समय घरों से बाहर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं है। तेज धूप और उमस के कारण सांस लेना भी दूभर हो रहा है। दिनभर लोग पसीने से तर-बतर रहते हैं और उमस भरी गर्मी से निजात पाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा।

बेहाल कर रही बिजली कटौती

गर्मी से राहत पाने के लिए पंखे, कूलर और एयर कंडीशनर ही एकमात्र सहारा हैं, लेकिन छितौनी में बिजली की लगातार और लंबी कटौती ने इन उपकरणों को भी निष्प्रभावी कर दिया है।

जनजीवन पर चौतरफा असर, बिजली कटौती का असर छितौनी के हर वर्ग पर पड़ रहा है। सेवानिवृत्त अध्यापक ओम प्रकाश गिरी ने बताया कि दैनिक जीवन प्रभावित - लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से चरमरा गई है। पानी की किल्लत भी एक बड़ी समस्या बन गई है। रामपुर जंगल के निवासी जितेन्द्र गिरी ने बताया कि बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों की परेशानी- छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति इस भीषण गर्मी में सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उन्हें लगातार पसीना और घबराहट हो रही है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। छितौनी कस्बा के व्यापारी संतोष रौनियार ने बताया कि व्यापारियों को नुकसान- छोटे दुकानदार और व्यापारी भी बिजली कटौती से बुरी तरह प्रभावित हैं। दुकानों में ग्राहक नहीं आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है।

अध्यापक सुशील कुमार ने बताया कि छात्रों की पढ़ाई बाधित- परीक्षाओं का समय नजदीक है, लेकिन बिजली न होने से छात्र रात में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं।

इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, जिससे उनकी तैयारी पर सीधा असर पड़ रहा है।

रोशन मौर्य का रेलवे में अवर अभियन्ता पद पर हुआ चयन

जौनपुर। (वेबवार्ता) बचपन से ही होनहार रहे रोशन मौर्य ने रेलवे में अवर अभियंता सिविल पद पर चयनित होकर परिवार सहित पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। बता दें कि रोशन जो जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर ग्राम मोलनापुर, छबीलेपुर विकास खण्ड करंजकला के मूल निवासी हैं। इनके पिता रमानन्द मौर्य जौनपुर के लोक निर्माण विभाग में स्टेनो हैं तथा दादा महातिम मौर्य उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक पद से अवकाश ग्रहण किये हैं। साथ ही रोशन के बड़े भाई डॉ. अंकित मौर्य सी.पी.डब्ल्यू.डी. में जे.ई. पद को सुशोभित कर रहे हैं। रोशन के चयन होने पर जहां परिवार में खुशी का माहौल कायम हो गया है, वहीं रोशन सहित उनके स्टेनो पिता रमानन्द मौर्य सहित उनके अवकाशप्राप्त दादा महातिम मौर्य को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।

नेट जेआरएफ परीक्षा उत्तीर्ण करके हिमांशु ने परिवार का बढ़ाया मान

धर्मापुर, जौनपुर। (वेबवार्ता) स्थानीय विकास खण्ड के ग्रामसभा कादीपुर पौना निवासी हिमांशु यादव ने नेट जे.आर.एफ. परीक्षा उत्तीर्ण करके परिवार सहित पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। इसकी जानकारी होने पर जहां परिवार में खुशी की लहर दौड़ गयी, वहीं उनके शुभचिन्तकों, रिश्तेदारों, परिचितों द्वारा लगातार बधाई दी जा रही है। बता दें कि हिमांशु उक्त गांव निवासी अजय यादव के होनहार पुत्र हैं। इन्होंने नेट जेआरएफ परीक्षा में 99.4वां अंक प्राप्त किया है। वहीं जानकारी होने पर अखिल भारतीय यादव महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव दिनेश यादव फौजी, जिला पंचायत सदस्य जनता यादव, समाजसेवी राकेश यादव सहित तमाम लोगों ने हिमांशु को बधाई देते हुये उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना किया। वहीं इस बाबत पूछे जाने पर हिमांशु ने अपनी इस सफलता का सारा श्रेय अपने गुरूजनों, माता, पिता एवं शुभचिन्तकों को दिया है।

एक सप्ताह से जला ट्रांसफार्मर, रामपुर खुर्द शोभा छपरा में दर्जनों घरों में अंधेरा, गर्मी से लोग परेशान

ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से इस समस्या का तत्काल समाधान करने की मांग की है।

नेबुआ नौरंगिया कुशीनगर । कुशीनगर के विद्युत उपकेंद्र कोटवा क्षेत्र में स्थिति गंभीर है। रामपुर खुर्द शोभा छपरा में एक सप्ताह से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। इससे क्षेत्र के दर्जनों घरों में बिजली आपूर्ति बाधित है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, यह पहली बार नहीं है। जब ट्रांसफार्मर जला है। पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। हर बार विद्युत कर्मचारियों ने ट्रांसफार्मर की मरम्मत कर इसे दोबारा लगाया, लेकिन समस्या बार-बार सामने आ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने विद्युत विभाग के कर्मचारियों को इस समस्या की सूचना दी है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गर्मी के मौसम में बिजली न होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात में अंधेरे में रहना और दिन में गर्मी झेलना मजबूरी बन गई है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से इस समस्या का तत्काल समाधान करने की मांग की है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द बिजली बहाल की जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके।

भाजपा जिला कार्यकारिणी की बैठक संपन्न

पडरौना कुशीनगर ।

भारतीय जनता पार्टी कार्यालय रविन्द्र नगर में बुधवार को जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय की अध्यक्षता में जिला पदाधिकारी बैठक सम्पन्न हुई जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव,कारगिल विजय दिवस,मन की बात और सोशल मीडिया पर विस्तृत चर्चा किया गया। जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा कि वर्ष 2026 के अप्रैल - मई में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रस्तावित है। राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य करने जा रहा है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि अपने अपने पंचायतों में मतदाता पुनरीक्षण के दौरान इस बात की चिंता करें कि सभी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो और एक फर्जी मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो पाए। जिलाध्यक्ष ने बताया कि 26 जुलाई को रविन्द्र नगर भाजपा कार्यालय में कारगिल विजय दिवस पर जिला स्तरीय संगोष्ठी आयोजित किया जाएगा। और रविवार 27 जुलाई को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम है जिसे सभी बूथों पर प्रभावी तरीके से प्रसारित हो इस बात के लिए प्रत्येक मण्डल में एक वरिष्ठ पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में सोशल मीडिया पर चर्चा करते हुए जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के फर्जी पदाधिकारी बनकर पार्टी और सरकार विरोधी बातें लिख रहे है जो कतई बर्दाश्त नहीं है। ऐसे लोगों की सूची बनाकर इनपर विधिक कार्यवाही की जाएगी। जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा कि विगत दिनों एक महिला नेत्री नूतन दूबे द्वारा फेसबुक लाइव आकर सरकार के खिलाफ अनाप-शनाप आरोप लगाया गया था जिसे मीडिया और सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष बताकर प्रसारित किया गया था यह कतई सच नहीं है। नूतन दूबे को विगत नगर निकाय चुनाव के दौरान ही दायित्व मुक्त कर दिया गया था। इस अवसर पर जिला महामंत्री राणा प्रताप राव,सुदर्शन पाल, सन्तोष दत्त राय, जिला उपाध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह, विजय कुमार शुक्ल, रमेश सिंह, डॉ विनोद भारती, दिवाकर मणि त्रिपाठी, जिला मंत्री विवेकानंद शुक्ल रामगोपाल गुप्ता, डॉ सीमा गुप्ता, रामसागर कुशवाहा, शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ क्षेत्रीय संयोजक सुरेन्द्र सिंह,जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनन्द,आई टी विभाग जिला संयोजक नमो नारायण मौर्य, हरि गोविंद रौनियार, धनंजय तिवारी, डॉ टी एन राव,धनंजय राय, शिवाकांत सिंह आदि उपस्थित रहे।

लायन्स क्लब जौनपुर मेन ने पौधरोपण करके बच्चों को दिया स्टेशनरी

जौनपुर।

एक पौधा मां और एक पौधा सन्तान के नाम लगायें : राजेशराज गुप्ता

एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाते हुए लायन्स क्लब जौनपुर मेन ने एक पेड़ मां और एक पेड़ सन्तान के नाम शीर्षक से स्थान एडप्टेड प्राथमिक विद्यालय राजेपुर निकट सरायख्वाजा पर पौधरोपण व स्टेशनरी वितरण कार्यक्रम किया।

इस दौरान विद्यालय परिसर सहित आस-पास 101 पौधे लगाये गये। साथ ही बच्चों व अभिभावकों को अपनी माँ व सन्तान के नाम एक एक पौधा लगाने और पर्यावरण का संरक्षण करने हेतु प्रेरित किया। आम, आंवला, जामुन, शीशम, पीपल, पाकड़, अमरूद, सागौन आदि के पौधे लगाये गये। वहीं स्कूली बच्चों को स्टेशनरी किट प्रदान की गयी जिसे पाकर उनके चेहरे खुशियों से खिल उठे। इस मौके पर संस्थाध्यक्ष सीए राजेश राज गुप्ता ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम का मतलब है कि यह पेड़ प्रकृति, पर्यावरण और पारिवारिक मूल्यों को जोड़ने वाला एक मजबूत सेतु है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सै. मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि यह एक प्रयास है जो हमारी मातृभूमि और प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान और समर्पण को दर्शाता है। एस.एम.सी. अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण के लिए हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। इस अवसर पर ग्राम प्रधान आनन्द सिंह, सचिव योगेश साहू, कोषाध्यक्ष रंजीत सिंह, प्रभाकर उपाध्याय, विजय बहादुर यादव, प्रियंका सिंह, हेमलता, शकुन्तला देवी, पुष्कर सिंह, बीना देवी, राधेश्याम मिश्रा सहित तमाम अभिभावक, छात्र-छात्राएं आदि उपस्थित रहे।

004

सहकारी गन्ना विकास समिति से यूरिया की कालाबाजारी की पुष्टि पर जिला कृषि अधिकारी ने की कार्रवाई

कुशीनगर ।

खड्डा क्षेत्र के गन्ना विकास समिति से यूरिया की कालाबाजारी को स्थानीय कृषकों ने रोका और सूचना जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मेनका सहित अन्य संबंधित को प्रेषित की। घटना सोमवार की रात लगभग 10:30 बजे की है। सचिव के द्वारा रात में उर्वरक की बिक्री की सूचना मिलने पर किस नाराज हो गया और उन्होंने बोलेरो में लगे हुए नौकरी उड़िया तथा एक टेंपो में 12 बोरी यूरिया को पकड़ लिया। खाद लदा हुआ वाहन थाना खड्डा लाया गया। मौके पर तहसीलदार खड्डा महेश कुमार एवं कृषि विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में दोनों वाहनों पर लगे हुए उर्वरक को नियमानुसार जमा करने की कार्रवाई की गई। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मेनका ने बताया कि जनपद में नत्रजनित उर्वरक की भारी मांग है। जनपद में सभी प्रकार के उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जिसके अंतर्गत 8272 मेट्रिक टन यूरिया, 3395 मेट्रिक टन फास्फेटिक उर्वरक, 3954 मेट्रिक टन एन पी के विभिन्न उर्वरक केंद्रों पर उपलब्ध है। इसी प्रकार 1978 मेट्रिक टन यूरिया देवरिया रैक प्राप्त हो रही है जिनको निजी एवं सरकारी समितियों पर कृषि विभाग के कार्मिकों की उपस्थिति में वितरित कराया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मेनका ने बताया कि प्रवर्तन के कार्रवाई लगातार जारी है दो यूरिया लदी गाड़ियों को सीज किया गया है तथा 12 विक्रेताओं के उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निलंबित किए गए है, तथा 19 उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।

पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार

देवरिया।(वेबवार्ता) बालिकाओं के प्रति अपराध के मामलों में कठोर कार्रवाई के संकल्प के साथ देवरिया पुलिस लगातार सक्रिय है। इसी क्रम में पॉक्सो एक्ट के गंभीर मामले में वांछित चल रहे अभियुक्त शशिकान्त कुमार गौड़ को थाना सुरौली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बुधवार को ठकुरदेवा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विक्रान्त वीर के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत हुई। अभियान की निगरानी अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सुनील कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी सदर अंशुमान श्रीवास्तव के कुशल पर्यवेक्षण में की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त शशिकान्त कुमार गौड़ पुत्र लोकनाथ गौड़, निवासी गोलौथा, थाना सुरौली, जनपद देवरिया के विरुद्ध थाना सुरौली में मु.अ.सं. 149/2025, धारा 64(1) BNS व 5j(2)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। पुलिस टीम ने अभियुक्त के पास से एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जिसे केस से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में लिया जा रहा है। पुलिस द्वारा अभियुक्त के खिलाफ विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष सुरौली हवलदार राम, उपनिरीक्षक अनिल कुमार तिवारी, कॉन्स्टेबल बेलाल अंसारी, दीपक मौर्य शामिल रहे।

डीएम ने सरस्वती विद्या मंदिर में किया मेधावी छात्रों का सम्मान, शिक्षा के साथ कर्तव्यनिष्ठा का दिया संदेश

देवरिया। आपकी सफलता सिर्फ आपकी नहीं होती, वह पूरे समाज, राज्य और देश की प्रेरणा बन जाती है। अगर हम अपने दायित्वों को ईमानदारी से निभाएं, तो यही राष्ट्रीय निर्माण की बुनियाद बनते है। यह भावपूर्ण संदेश बुधवार को जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय देवरिया खास में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि दिया।

कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय के माधव सभागार में हुआ, जहाँ डीएम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को लेपटॉप, टेबलेट, टाईटन घड़ी और मां सरस्वती की कांस्य प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान उनके शब्दों में केवल प्रशंसा नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिक गढ़ने का आह्वान झलक रहा था। उन्होंने कहा, हमारा संयुक्त अस्तित्व ही भारत की विराट संस्कृति का प्रतीक है। सफलता का अर्थ केवल निजी लाभ नहीं, बल्कि उस ज्ञान और ऊर्जा को समाज के विकास में लगाना है। भारतीय परंपरा परोपकार और वैश्विक बंधुत्व की भावना से जुड़ी है, जो हमें विश्व में विशिष्ट बनाती है।

कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। विद्यालय के प्रधानाचार्य अनिरुद्ध सिंह ने मुख्य अतिथि का परिचय प्रस्तुत किया और कार्यक्रम की पृष्ठभूमि साझा की। इस समारोह में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में जनपद में सर्वोच्च स्थान पाने वाले आयुष सिंह को लेपटॉप, वहीं दूसरे स्थान पर रहे कार्तिकेय जोशी को टैबलेट और टाईटन घड़ी से सम्मानित किया गया। कक्षा 12 में सर्वोच्च स्थान पाने वाले शशांक सिंह को भी विशेष उपहार प्रदान किए गए। डीएम दिव्या मित्तल ने सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मेहनत, अनुशासन और प्रेरणा से ही महान लक्ष्य हासिल होते हैं।

उन्होंने युवाओं से आवाह्न किया कि महापुरुषों से प्रेरणा लेकर जीवन को समाज के लिए उपयोगी बनाएं। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने डीएम का स्वागत किया, और प्रबंधक मुन्नी लाल शर्मा ने आभार ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन अशोक यादव ने किया और मनोज कुंदन ने मीडिया समन्वयक की भूमिका निभाई। इस अवसर पर उपप्रधानाचार्य अखिलेश दीक्षित, जितेन्द्र मिश्र, दीलीप श्रीवास्तव, रितेश मिश्र, अमरेन्द्र उपाध्याय, डीएन पाठक, मनोज नायक सहित विद्यालय के अन्य शिक्षक और अभिभावक उपस्थित रहे।

नवजात कन्याओं का हुआ तीज सेलिब्रेशन

पड़रौना, कुशीनगर । (वेबवार्ता)मारवाड़ी युवा मंच चेतना महिला शाखा पडरौना द्वारा मंच के राष्ट्रीय प्रकल्प कन्या भ्रूण संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी अस्पताल जाकर नवजात कन्याओं का तीज सेलिब्रेशन किया गया जो कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराई को रोकने और बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती है। साथ ही नवजात कन्या की मां पिता को कन्या क जन्म के लिए बधाई दी गई। मंच अध्यक्ष मीनू जिंदल ने बताया कि यह कार्यक्रम न केवल कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में मदद करता है, बल्कि यह बालिकाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी सहायक है। तीज उत्सव में जन्मजात कन्याओं को आकर्षक उपहार दिया गया तथा पूरे अस्पताल में मिठाई वितरित की गई। कार्यक्रम उपरांत अस्पताल परिसर में ही वृक्षारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में मंत्री रश्मि टिंबरेवाल कोषाध्यक्ष प्रिया टिंबरेवाल पदमा अग्रवाल प्रीति सराफ मधु नथानी बबीता टिंबरेवाल नीलम रुंगटा आदि सम्मिलित रहे।

असम (सक्षम भारत) कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ गुवाहाटी मेंराजनीतिक मामलों की समिति, पीसीसी पदाधिकारी, सांसद, विधायक, फ्रंटल संगठन प्रमुख और जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। छाया -सक्षम भारत

मानसून सत्र के तीसरे दिन भी जारी रहा हंगामा, लोकसभा में राष्ट्रीय खेल शासन बिल पेश

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने भी बुधवार को संसद के बाहर बिहार के एसआईआर मुद्दे पर विशेष प्रदर्शन किया। इस बीच, सूत्रों के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तृत चर्चा 29 जुलाई को राज्यसभा में निर्धारित की गई है, जिसके लिए 16 घंटे का समय आवंटित किया गया है। लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर बुधवार को भी सदन में हंगामा किया, जिसके कारण दो बार के स्थगन के बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में बुधवार को सरकार ने एक विधेयक पेश किया जिसके प्रावधानों के दायरे में भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) भी आएगा तथा इसमें भले ही बीसीसीआई की स्वायत्तता को बरकरार रखा गया है किंतु उससे जुड़े विवादों का निस्तारण राष्ट्रीय पंचाट के जरिये करवाने का प्रस्ताव है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इन प्रावधानों वाला सदन में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 पेश किया। खेलों में डोपिंग रोधी उपायों को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाए गए एक कानून में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) के सुझावों के मुताबिक बदलाव शामिल करते हुए एक संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सदन में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक, 2025 पेश किया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के प्रमुख घटक जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद गिरिधारी यादव ने बुधवार को लोकसभा में दावा किया कि पिछले 11 वर्षों में बिहार को एक भी नई ट्रेन नहीं मिली, जबकि केंद्र में राजग की सरकार लाने में इस प्रदेश की बड़ी भूमिका है। इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार ने बिहार के लिए पांच नई 'अमृत भारत' रेलगाड़ियां चलाई हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने वाले सांसदों पर निर्णायक कार्रवाई की चेतावनी देते हुए बुधवार को जोरआजमाइश कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा कि वे सड़कों का आचरण संसद के भीतर कर रहे हैं, जबकि वो 'माननीय' हैं और उनका व्यवहार 'माननीय' जैसा ही होना चाहिए। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्षी दलों के विरोध के चलते राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार को बाधित रही और दो बार स्थगन के बाद दोपहर दो बज कर पांच मिनट पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

विपक्ष पहलगाम,ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में चर्चा की मांग की, कहा- सुनिश्चित हो पीएम की मौजूदगी

नई दिल्ली ।

ऑपरेशन सिंदूर पर अगले हफ्ते संसद में शब्द-संग्राम छिड़ेगा. सोमवार को लोकसभा और मंगलवार को राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होगी. मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्षी सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर सरकार की घेराबंदी की थी. विपक्ष के हंगामे के बीच उसी दिन संसद के दोनों सदनों में सरकार ने साफ कर दिया था कि वह चर्चा के लिए तैयार है. विपक्ष चर्चा के आखिर में पीएम नरेंद्र मोदी के जवाब पर अड़ा हुआ था. पीएम मोदी के ब्रिटेन और मालदीव दौरे पर होने के कारण विपक्ष ने अपना मिशन ऑपरेशन सिंदूर अगले हफ्ते तक टाल दिया था और सत्र के दूसरे दिन से रणनीति

■ ऑपरेशन सिंदूर- लोकसभा में 28, राज्यसभा में 29 जुलाई को चर्चा , दोनों सदनों में 16-16 घंटे बहस

■ विपक्ष के हंगामे से लगातार तीसरे दिन सदन नहीं चला

बदलते हुए बिहार वोटर लिस्ट के मुद्दे पर अपने वार को धार देना शुरू किया था. अब इस हफ्ते के आखिर में पीएम मोदी के विदेश से लौटने के बाद सोमवार और मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में चर्चा होगी. राज्यसभा की व्यापार सलाहकार समिति (बीएसी) की बैठक में बुधवार को

विपक्ष ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की। विपक्ष ने कहा कि इस मुद्दे पर राज्यसभा में अगले हफ्ते से दो दिन तक 16 घंटे की चर्चा होनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए। यह बैठक मानसून सत्र के दौरान हुई, जिसमें विभिन्न दलों के नेता, राज्यसभा में सदन के नेता जे. पी. नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने की। बैठक के बाद कांग्रेस के राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी ने बताया कि विपक्ष ने एक सुर में मांग की कि पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा अगले हफ्ते से शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि लोकसभा में इस पर चर्चा शुरू होने के एक दिन बाद राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए। प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह एक सामान्य बहस होनी चाहिए, कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग की और सरकार ने आश्वासन दिया है कि प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि संसद के दोनों सदनों में पहलगाम हमले, बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा (एसआईआर) और अन्य मुद्दों को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है, जिसकी वजह से कार्यवाही बार-बार स्थगित की जा रही है।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग हुआ सक्रिय

नई दिल्ली ।

जल्द होगी चुनाव की घोषणा

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद भारत निर्वाचन आयोग एक्शन मोड में आ गया है। आयोग ने 2025 में होने वाले नए उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों की शुरुआत कर दी है। आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सभी जरूरी तैयारियों के पूरा होने के बाद उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीखों की जल्द ही घोषणा की जाएगी। धनखड़ ने सोमवार को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को स्वीकार कर लिया। गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई 2025 को अधिसूचना जारी कर उनके इस्तीफे की जानकारी दी। इसके बाद चुनाव आयोग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उसे उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। यह चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के अंतर्गत कराया जाता है। आयोग ने बताया कि निर्वाचक मंडल की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। इसके साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आयोग ने बताया कि पिछले उपराष्ट्रपति चुनावों से संबंधित रिकॉर्ड और अनुभवों की भी समीक्षा की जा रही है।

25 बार कह चुके हैं ट्रंप कि युद्धविराम मैंने कराया, राहुल गांधी बोले- क्यों चुप हैं प्रधानमत्री मोदी?

नई दिल्ली । लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजिया बयान पर तीखा हमला बोला। ट्रंप ने दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम उनकी पहल पर हुआ। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दे पा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, -पीएम मोदी बोल ही नहीं सकते कि युद्धविराम ट्रंप ने कराया। लेकिन सच्चाई यही है और पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप ने ही युद्धविराम कराया है।- उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि युद्ध विराम कराने वाला ट्रंप कौन होता है? यह भारत का आंतरिक मामला है और इस पर कोई बाहरी देश दखल कैसे दे सकता है।

देश को सच्चाई जानने का हक है- राहुल

राहुल गांधी ने आगे कहा कि विपक्ष सिर्फ युद्धविराम के मुद्दे पर चर्चा

नहीं चाहता, बल्कि डिफेंस और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कई अहम मामलों पर भी बात करना जरूरी है। उन्होंने कहा, -हालात अच्छे नहीं है और पीएम मोदी एक बार भी जवाब नहीं दे रहे। ट्रंप 25 बार कह चुके हैं कि मैंने युद्धविराम कराया, लेकिन मोदी चुप हैं।- कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश को सच्चाई जानने का हक है। उन्होंने सरकार से स्पष्ट जवाब की मांग की।

हिंदुस्तान में चुनाव चोरी किए जा रहे...एसआईआर को लेकर ईसी पर राहुल गांधी का आरोप

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर हमला बोला है. राहुल गांधी ने बुधवार को संसद परिसर में पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की. हमने चुनाव आयोग से सवाल पूछे कि वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने मतदाता सूची नहीं दिखाई. हमने कहा, वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, लेकिन इन्होंने वीडियोग्राफी का कानून ही बदल दिया. महाराष्ट्र में एक करोड़ नए वोटर आए थे. इन्होंने इलेक्शन चोरी किया. कर्नाटक में हमने थोड़ी रिसर्च की है. इसे भयंकर चोरी है. कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा कि कैसे चोरी की जाती है. चुनाव आयोग को दिखाऊंगा. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, इनको पता लग गया है कि हम इनका गेम समझ गए हैं. हमने एक सीट चुनी और उसमें गहन तहकीकात की. ये मतदाता सूची कागज में देते हैं, लेकिन जो पेपर में वोटर लिस्ट दी जाती है, उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता. हमने एक संसदीय सीट की पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली. उसको डिजिटल प्रारूप में बदला. इसमें हमें छह महीने लगे, लेकिन हमने इनका पूरा का पूरा सिस्टम निकाल लिया है. राहुल गांधी ने कहा, ये कैसे करते हैं, वोट कैसे होता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं. अब इन्होंने बिहार का पूरा का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे. वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से तैयार करेंगे. हिन्दुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं और देश की हकीकत है. राहुल गांधी पहले ही महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा चुके हैं.

एसआईआर के खिलाफ नीतीश के सांसद का फूटा गुस्सा

'चुनाव आयोग को कुछ नहीं पता, हम पर थोप दिया'

पटना। जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने बुधवार को बिहार में मतदाता सूचियों के चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर कड़ी आपत्ति जताई। दिल्ली में बोलते हुए, यादव ने इस प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग की आलोचना की और कहा कि आयोग को बिहार के इतिहास और भूगोल का व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। एएनआई से बात करते हुए, यादव ने दस्तावेज जमा करने की एक महीने की समय सीमा को अव्यावहारिक बताया और आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करने में 10 दिन लगने का अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा किया। गिरधारी यादव ने प्रवासी मतदाताओं, जिनमें अमेरिका में रहने वाला उनका अपना बेटा भी शामिल है, को दी गई समय सीमा के भीतर

हस्ताक्षर की आवश्यकताओं का पालन करने में आने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डाला। यादव ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया जमीनी हकीकत पर विचार किए बिना लागू की गई है, और सुझाव दिया कि इस प्रक्रिया के लिए कम से कम छह महीने का समय दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को कोई व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। उसे न तो बिहार का इतिहास पता है और न ही भूगोल। मुझे सारे दस्तावेज इकट्ठा करने में 10 दिन लग गए। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अमेरिका में रहता है। वह सिर्फ एक महीने में हस्ताक्षर कैसे कर पाएगा? यह (एसआईआर) हम पर जबरदस्ती थोपा गया है। इसके लिए कम से कम 6 महीने का समय दिया जाना चाहिए था... मैं अपनी निजी राय दे रहा हूं। पार्टी क्या कह रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता... यही सच्चाई है। अगर मैं सच नहीं बोल सकता, तो सांसद क्यों बना? इस बीच, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर चिंता जताई है और इस प्रक्रिया के तेजी से क्रियान्वयन पर सवाल उठाए हैं।

जम्मू के 12 जिलों में अचानक बाढ़ आने का खतरा, हाई अलर्ट पर अगले 24 घंटे

जम्मू-कश्मीर । जम्मू-कश्मीर में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए 12 जिलों में अचानक बाढ़ का खतरा जताया है। इससे पहले ही प्रदेश में भारी बारिश को लेकर तीन दिनों का अलर्ट जारी किया गया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी बाढ़ मार्गदर्शन बुलेटिन में बताया गया है कि इन जिलों में कम से मध्यम खतरा है कठुआ, सांबा, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, जम्मू, राजौरी, पुंछ, बारामुला, अनंतनाग। इन इलाकों में भारी बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे भूस्खलन और चट्टानें खिसकने का भी खतरा है।

कानपुर-मेरठ समेत देश के 150 शहरों के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी

कानपुर ।

कानपुर, मेरठ, आगरा समेत देश के150 शहरों के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई थी। जिसमें लिखा गया कि हम आपको यह सूचना दे रहे हैं कि स्कूल परिसर भवन में कई बम छिपाकर रखे गए हैं। विस्फोटकों को बड़ी कुशलता से छिपाया गया है। इसमें आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार दो नामों को लिखा गया था। इसके बाद एटीएस सक्रिय हो गई और स्कूल प्रबंधन से जानकारी जुटाना शुरू किया। इससे पहले भी कई स्कूलों को ईमेल से ही धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन पुलिस आरोपितों को तलाश नहीं सकी। केशवनगर स्थित गुलमोहर पब्लिक स्कूल, किदवई नगर के ब्लाक के सेंट थामस इंटर कालेज और रेलबाजार क्षेत्र के डान बास्को स्कूल को ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद से स्कूल प्रबंधन में खलबली मच गई। लेकिन संचालक व प्रबंधकों ने पहले मामले को इसलिए छिपाया कि बच्चों के अभिभावक परेशान न हो जाएं, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसी धमकियां देशभर के मेरठ, आगरा, कानपुर समेत 150 जिलों के स्कूलों को दी गई। इसके बाद एटीएस सक्रिय हुई। शहर में एटीएस की टीम ने तीनों स्कूलों के प्रबंधन से जानकारी जुटानी शुरू कर दी। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि जिन स्कूलों को धमकी मिली वहां से जानकारी की जा रही है।

गाजियाबाद में चार-चार देशों के फर्जी दूतावास, यूपी एसटीएफ ने फ्रॉड हर्षवर्धन जैन को किया गिरफ्तार

लखनऊ । देश में फर्जी बैंक व यूनिवर्सिटी के बाद अब दूतावास भी संचालित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में फर्जी दूतावास से दूसरे देशों में जाने के लिए लोगों को वीजा तक मुहैया कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गाजियाबाद के कविनगर से वेस्ट आर्कटिक का फर्जी दूतावास संचालित करने वाले फ्रॉड हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने गाजियाबाद में केस दर्ज कराया है और अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उसके पास से 44 लाख 70 हजार रुपये, विभिन्न देशों की विदेशी मुद्रा, 20 डिप्लोमेटिक गाड़ियों की नंबर प्लेट, चार डिप्लोमेटिक नम्बर प्लेट लगी हुई गाड़ियां आदि सामान बरामद हुआ है। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने गाजियाबाद के हर्ष वर्धन जैन पुत्र जेडी जैन निवासी 45 केबी कविनगर को किराए के मकान में वेस्ट आर्कटिक का अवैध दूतावास संचालित करते पकड़ा। वह अपने वेस्ट आर्कटिक, सेबोर्गा, पोल्विया और लोडोनिया आदि देशों का काउंसिल या राजदूत बताता था। वह काल्पनिक देशों का दूतावास का प्रमुख बताकर लोगों को ठगता था। उसने सेबोर्गा देश के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनवाए थे। वह अपना रूतबा कायम करने के लिए कई डिप्लोमेटिक नम्बर प्लेट लगी लग्जरी गाड़ियों से चलता है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कई अन्य गणमान्य लोगों के साथ अपनी फोटो का भी प्रयोग करता है। इसका मुख्य काम कंपनियों और प्राइवेट व्यक्तियों को बाहर के देशों में काम दिलाने के नाम पर दलाली करना तथा शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला रैकेट चलाना है। हर्षवर्धन के पहले चंद्रास्वामी और अदनान खगोशी जैसे इंटरनेशनल आर्म्स डीलर से भी सम्पर्क की जानकारी मिली है। 2011 में हर्षवर्धन के पास के एक अवैध सैटेलाइट फोन भी बरामद हुआ था। जिसका केस भी कविनगर में किया गया था। एसटीएफ ने जब छापा मारा तो हर्षवर्धन के मकान उसके ससुर आनंद जैन, भाटिया मोड़ निवासी ईश्वर सिंह और घरेलू सहायक हेमंत कुमार रावंशी भी मिले। ईश्वर और हेमंत को एसटीएफ ने गवाह बनाया।

हमें गलत शव मिले, अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर लंदन के दो पीड़ित परिवारों का दावा

नई दिल्ली। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अपनों को खोने वाले दो पीड़ित परिवारों ने गलत शव मिलने का दावा किया है। उनका कहना है कि जो शव उन्हें दिए गए, उनकी डीएनए रिपोर्ट परिवार से मेल नहीं खा रहे हैं। दोनों ब्रिटिश परिवारों का पक्ष रखने वाले वकील जेम्स हेली का कहना है कि 12 जून को हुए प्लेन क्रैश के बाद 12 शवों को ब्रिटेन भेजा गया था। हालांकि दो परिवारों को मिले शवों का डीएनए अलग है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जाने वाला एअर इंडिया का विमान-ए171 कुछ सेकेंड बाद ही क्रैश हो गया था। विमान हादसा इतना भयानक था कि 1 यात्री को छोड़कर प्लेन में मौजूद सभी लोग जिंदा जल गए।

पीएम मोदी 4 दिवसीय यात्रा के लिए ब्रिटेन-मालदीव हुए रवाना

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो देशों - यूनाइटेड किंगडम और मालदीव के दौरे पर रवाना हुए। यह दौरा 23 से 26 जुलाई तक चलेगा, जिसमें मोदी जी पहले यूनाइटेड किंगडम का आधिकारिक दौरा करेंगे और उसके बाद मालदीव की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 23 और 24 जुलाई को यूनाइटेड किंगडम में रहेंगे, जहां वे ब्रिटेन के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई अहम बातचीत करेंगे। इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक, रक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। यूनाइटेड किंगडम दौरे के बाद, प्रधानमंत्री मोदी 25 और 26 जुलाई को मालदीव की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। मालदीव के दौरे के दौरान वे

द्विपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा, पर्यटन और विकास सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को दोनों देशों के साथ भारत के रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

प्रदेश की हर गली, मोहल्ले में स्वच्छता की जो सुगंध फैली, उसमें छिपी हुई सफाई कर्मचारियों की मेहनत - मुख्यमंत्री सैनी

चण्डीगढ़ ।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश की हर गली, हर मोहल्ले में स्वच्छता की जो सुगंध फैली है, उसमें सफाई कर्मचारियों की मेहनत छीपी हुई है। सफाई कर्मचारी सिर्फ कर्मचारी नहीं है, प्रदेश के शहरों और गांवों की रीढ़ है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यह बात आज चण्डीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए सफाई कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए कही। संत कबीर जयंती के अवसर पर सफाई कर्मचारियों के वेतन में 2100

प्रदेश के शहरों और गांवों की रीढ़ है सफाई कर्मचारी
सफाई कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी को लेकर मुख्यमंत्री का जताया आभार
सफाई कर्मचारियों के बिना स्वच्छ हरियाणा की कल्पना भी असंभव

रूपये बढ़ोतरी होने पर आज प्रदेश भर से सफाई कर्मचारी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने आए थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को

शिवरात्रि की बधाई दी। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं सफाई कर्मचारियों को सलाम करता हूं, जो हर गली, मोहल्ले और सड़क को स्वच्छ और सुंदर बनाने में दिन-रात जुटे रहते हैं। उन्होंने कहा कि आप हमारे स्वास्थ्य के रक्षक व वातावरण के प्रहरी हैं। आपके बिना स्वच्छ हरियाणा की कल्पना भी असम्भव है। आपका काम केवल कचरा उठाना नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन की नींव रखना है, जो हरियाणा के हर नागरिक के लिए अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीवर की सफाई का कार्य जोखिम भरा होता है। आप अपना जीवन खतरे में डालकर यह कार्य करते हैं। आपका यह योगदान सराहनीय है। स्वच्छता चाहे शरीर की हो या अपने आस पास के परिवेश की हो, इसका सीधा सम्बन्ध हमारे स्वास्थ्य से है। हमारे गौरव और गरिमा से है। हमारे सामाजिक एवं आर्थिक विकास से है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छता को भगवान के बाद दूसरा स्थान देते थे। वे स्वयं झाड़ू लगाकर लोगों में सफाई के प्रति चेतना पैदा करते थे। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की जयंती पर 2 अक्तूबर, 2014 से 'स्वच्छ भारत मिशन' की शुरुआत की, तो देश ने एक नया संकल्प लिया। इस संकल्प को पूरे समर्पण से निभाने का श्रेय सबसे पहले सफाई कर्मचारियों को जाता है। आप न सिर्फ हमारे गांव व शहरों की सफाई करते हैं, बल्कि देश की सोच को भी स्वच्छ बनाते हैं।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 'सबसे स्वच्छ शहर सम्मान' के तहत सोनीपत को 'मिनिस्टीरियल स्टार' अवॉर्ड मिला है। इसी तरह 50 हजार से 3 लाख की आबादी वाली श्रेणी में करनाल शहर ने देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शहरी सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर 17 हजार रुपये मासिक तथा ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ाकर 16 हजार रुपये मासिक किया गया है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों को उनकी ड्यूटी पर मृत्यु होने की स्थिति में 5 लाख रुपये और सीवरेज में काम करते समय मृत्यु होने की स्थिति में 10 लाख रुपये की बीमा राशि का प्रावधान किया गया है। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि सफाई कर्मचारी बहादुर योद्धा है जो स्वच्छता के लिए हर समय तैयार रहते है। आज डीएससी समाज के बच्चों को नौकरियां मिल रही है। हमारी सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण व भलाई के लिए वचनबद्ध है।